भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 117
मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024/12अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर शामिल करना

***117. श्री काली चरण सिंहः**
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पंचायत स्तर पर मत्स्यिकी सहकारी समितियों की तर्ज पर डेयरी के समान व्यवहार्य सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है;

(ख) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर से सम्बद्ध करके उन्हें डिजिटल बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो आज तक देश में ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल की गई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या का विशेषतः उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण के कार्य में हुई प्रगति और पंचायत-स्तरीय सहकारी समितियों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ) तक: सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं 117 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने की योजना को मंजूरी दी है । इस योजना में अगले पांच वर्षों में डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (M-PACS), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी । इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा का उल्लेख करते हुए दिनांक 19.09.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) लॉन्च की गई है ।

(ख) कंप्यूटरीकरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सशक्त करने के लिए भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें सभी कार्यशील PACS को एक ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) से लिंक किया जा रहा है । ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, कॉमन एकाउंटिंग प्रणाली (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से PACS के निष्पादन में दक्षता लाती है।

(ग) अब तक, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 67,930 PACS के कंप्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसके लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 699.89 करोड़ रुपये और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाबार्ड को 165.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं । दिनांक 21.11.2024 तक कुल 40,727 पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 2,505 पैक्स शामिल हैं । इस परियोजना के अंतर्गत पैक्स के डिजिटलीकरण की प्रगति, जैसे ERP ऑनबोर्डिंग, हार्डवेयर डिलीवरी, गो-लाइव, आदि की उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार प्रगति **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है, पैक्स डिजिटलीकरण की प्रगति का ब्योरा **अनुलग्नक** में संलग्न है। इस परियोजना के तहत गुजरात राज्य के स्वीकृत 5,754 पैक्स सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पैक्स को 3.91 लाख रुपये (लगभग) प्रति पैक्स की सहायता जिसमें हार्डवेयर (1,22,158/- रुपये), सॉफ्टवेयर (72,103 रुपये), प्रशिक्षण (10,198 रुपये), सपोर्ट सिस्टम की स्थापना (1,86,910 रुपये) की लागत शामिल है । इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में कुल 115 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

*****

अनुलग्नक

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत पैक्स डिजिटलीकरण की राज्य-वार प्रगति

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पैक्स	ऑनबोर्ड किए गए ERP	पैक्स की संख्या जहां हार्डवेयर डिलीवर किए गए	ERP -गो लाइव
1.	महाराष्ट्र	12,000	9,161	8,000	5,570
2.	राजस्थान	6,781	3,025	5,492	1,876
3.	गुजरात	5,754	3,838	5,752	2,216
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,505	3,062	2,429
5.	कर्नाटक	5,491	487	5,491	43
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,524	4,534	4,513
7.	तमिलनाडु	4,532	4,494	4,532	4,332
8.	बिहार	4,495	4,043	4,475	3,702
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	148	1,647	61
10.	पंजाब	3,482	1,580	3,420	627
11.	आंध्रप्रदेश	2,037	30	2,037	29
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,019	2,024	1,994
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	829	870	616
14.	झारखंड	1,500	1,403	1,500	1,403
15.	हरियाणा	710	687	710	633
16.	उत्तराखंड	670	185	670	185
17.	असम	583	567	583	532
18.	जम्मू और कश्मीर	537	532	535	529
19.	त्रिपुरा	268	247	268	241
20.	मणिपुर	232	23	-	18
21.	नागालैंड	231	33	231	33
22.	मेघालय	112	108	109	107
23.	सिक्किम	107	104	107	101
24.	गोवा	58	32	58	27
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	44	46	43
26.	पुड्डुचेरी	45	31	45	31
27.	मिजोरम	25	25	25	24
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	14	14	13
29.	लद्दाख	10	9	10	8
30.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	-	4	-
	कुल	**67,930**	**40,727**	**56,251**	**31,936**

दिनांक 21.11.2024 की स्थिति के अनुसार